



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 5 अप्रैल, 2006/15 चैत्र, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 5 अप्रैल, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्न० बिल, 1-25/2006.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 14) हिमाचल प्रदेश विधान

सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / -
(जे० आर० गाजेंटा)
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा ।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) संक्षिप्त नाम।
106 है।

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 10 के स्थान पर धारा 10 का निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“10. सिविल न्यायालयों की प्रारम्भिक अधिकारिता.—इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जिला न्यायाधीश के न्यायालय को समस्त मूल सिविलवादों में अधिकारिता होगी, जिनका मूल्य उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा नियत किया जा सकेगा।” ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) की धारा 10 के अधीन जिला न्यायाधीश के न्यायालय को उन सभी मूल सिविल वादों में अधिकारिता प्राप्त है जिनका मूल्य दस लाख रूपए से अधिक नहीं है और सभी मूल सिविल वाद, जिनका मूल्य दस लाख रूपए से अधिक है, माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित किए जा रहे हैं और उसके द्वारा उनका विचारण किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि उच्च न्यायालय में अत्याधिक मामले लम्बित पड़े हैं और सिविल वादों का निपटारा करने में असाधारण विलम्ब हो रहा है क्योंकि सिविल वाद के सुनवाई किए जाने योग्य हो जाने से पूर्व साक्ष्य को अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी इंगित किया है कि सिविल वाद मुकद्दमेंबाजी की एक शाखा का गठन करते हैं, जिनका, विधि के अधीन, अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा अधिक सुविधा से और शीघ्रता से निपटारा किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि न्यायमूर्ति मालिमथ समिति ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बहुत से उपायों की भी सिफारिशें की थीं और उनमें से एक उपाय सिविल वादों की बाबत उच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता को समाप्त करने से सम्बन्धित रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, जो आरम्भिक अधिकारिता वाला प्रधान न्यायालय है, की मूल अधिकारिता से सम्बन्धित मामले पर विचार किया है और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 के प्रतिस्थापन के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए संकल्प किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, मामले पर विचार किया गया और तदनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 को प्रतिस्थापित करने तथा माननीय उच्च न्यायालय को समय-समय पर धारा 10 के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा समस्त मूल सिविल वादों में जिला न्यायाधीश के न्यायालय की धन सम्बन्धी अधिकारिता को नियत करने हेतु, सशक्त करने का विनिश्चय किया गया। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम का संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

वीरमद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख.....2006.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 माननीय उच्च न्यायालय को समस्त सिविल वादों में, जिनमें जिला न्यायाधीश के न्यायालय को विनिश्चय करने की अधिकारिता होगी, अधिसूचना द्वारा मूल्य नियत करने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2006

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का 23) का और संशोधन करने के लिए
विधेयक।

वीरमद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख:.....2006.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2006

**THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT)
BILL, 2006**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No.23 of 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-Seventh Year of the Republic of India, as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Courts Short title
(Amendment) Act, 2006.

23 of 1976

2. For section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976, Amendment
the following shall be substituted, namely:— of section 10.

“10. Original jurisdiction of Civil Courts.—Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, the Court of District Judge shall have jurisdiction in all original civil suits, the value whereof may be fixed by a notification issued by the High Court.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, the Courts of District Judge have the jurisdiction in all original civil suits, the value whereof does not exceed ten lakh rupees, under section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No.23 of 1976) and all original civil suits, the value whereof exceeds rupees ten lakh are being instituted in and tried by the High Court. The Hon'ble High Court has intimated that there is huge pendency of cases in the High Court and disposal of civil suits is being inordinately delayed for the reason that the evidence is required to be recorded before a civil suit becomes ripe for hearing. The Hon'ble High Court has also pointed out that civil suits constitute one branch of litigation which, under law, can very conveniently and expeditiously be disposed of by subordinate civil courts and has further stated that Justice Malimeth Committee had also recommended a number of measure for speedy disposal of cases and one such measure related to abolition of original jurisdiction of the High Courts with respect to civil suits. The Hon'ble High Court has considered the matter regarding original jurisdiction of the District Judge being the principal court of original jurisdiction and resolved to move the State Government for substitution of section 10 of the Act *ibid*. In view of the reasons given by the High Court, the matter has been considered and it has been decided to substitute section 10 of the Act *ibid* accordingly and to empower the High Court to fix the pecuniary jurisdiction of the Court of District Judge in all original civil suits, by notification issued under section 10 from time to time. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Shimla :

The, 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the High Court to fix value in all original civil suits, by notification, which the court of District Judge shall have the jurisdiction to decide. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2006**A****BILL**

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No.23 of 1976).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

Shimla-171 002 :

The.....,2006.